

आमूल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 24

लखनऊ, सोमवार 28 सितम्बर 2026 सा 06 अक्टूबर 2026 तक

पृष्ठ—8

मूल्य : एक रुपया

चुनाव आयुक्तों ने दी सफाई

नई दिल्ली। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खोजी रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद को समाप्त करने के लिए शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने एक साथ बैठक की और सभी मुद्दों पर सफाई दी। एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर पूर्ण आयोग की बैठक हुई, जिसके बाद सभी मुद्दों पर सफाई दी गई। आयोग की ओर से कहा गया कि अखबार की रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों की ओर से असहमति जताने का जिक्र किया गया है वह एसआईआर को लेकर नहीं है। यह भी कहा गया कि एसआईआर आम सहमति से लिया गया फैसला था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को हुई बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल हुए। बैठक में विवाद से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया। कहा गया कि दो चुनाव आयुक्तों संघ और जोशी ने कैबिनेट सचिव को जो चिट्ठी भेजी थी, वह एसआईआर या चुनाव आयोग के किसी फैसले से जुड़ी नहीं थी, बल्कि चुनाव पैनल में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधि

कारी के कामकाज से संबंधित थी। शनिवार को हुई आयोग की पूर्ण बैठक के दौरान अंदरूनी मतभेद की खबरों को खारिज किया गया और कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों पर बिंदुवार सफाई दी गई। आयोग ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन



पुनरीक्षण यानी एसआईआर सहित सभी अहम फैसले पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने ने एकजुटता दिखाते हुए अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शनिवार को इन मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि घोषित फैसलों को पूरे आयोग की मंजूरी मिली हुई थी। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 90 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों

पर 98 बार आपत्ति जताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग में मनमानी करने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे देश में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। बहरहाल, आयोग ने गोवा में उन ६७ वोटों के मामले पर भी बात की, जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। आयोग ने कहा कि गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बूथ लेवल अधिकारियों को घर घर जाकर उनके फॉर्म इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। ६७ मतदाताओं में से ८१ ने नाम शामिल करवाने के लिए पहले ही फॉर्म छह भर दिया था। शनिवार की बैठक में आयोग ने अपने अंदरूनी कामकाज को बेहतर बनाने के लिए भी कई उपाय बताए। तय किया गया कि अब आयोग की सभी बैठकों का एजेंडा पहले ही भेजा जाएगा और बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा जारी किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि कमिश्नरों की ओर से अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा।

दो चुनाव आयुक्तों से मतभेद की खबरों के बीच दिल्ली में ३० को 'इंडिया' ब्लॉक की बैठक

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मनमाने तरीके से काम करने की 'इंडियन एक्सप्रेस' में आई रिपोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त के दो चुनाव आयुक्तों से मतभेद की खबरों के बीच विपक्षी गठबंधन यानी 'इंडिया' ब्लॉक की एक मीटिंग तय होने की खबर है। शनिवार को बताया गया कि बुधवार, ३० सितंबर को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो सकती है। ममता बनर्जी ने इस बैठक की पहल की है। उन्होंने करीब ३० साल के बाद सीपीएम महासचिव एमए बेबी से बात की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी विपक्ष की बैठक करने और साझा आंदोलन करने की गुजारिश की थी। इस बीच राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल भाजपा के लिए भर्ती करने में किया गया। फिर मोदी और शाह ने उन्हें अंपायर बनाकर भारत के चुनावों में मैच फिक्सिंग

का जिम्मा सौंप दिया। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें 'वैनिश कुमार' तक कह दिया है। हालांकि एक तरफ ममता बनर्जी और



कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि सिर्फ क करोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ही ज्ञानेश कुमार को हटा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सीजेपी कोई ठोस चुनौती दे, तो वे ज्ञानेश कुमार को हटा सकते हैं, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, लेफ्ट आदि की बैठक से पहले यह बयान नुकसानदेह है। गौरतलब है कि सीजेपी ने दो अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान किया है।

उप्र में राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के लिए जोड़तोड़ लामबंदी तेज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में जोड़तोड़ और लामबंदी तेज हो गई है। राज्यसभा की 90 सीटों के लिए 96 अक्टूबर और विधान परिषद की 99 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) ही अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में हैं। ऐसे में दोनों दलों में उम्मीदवारों के चयन और रणनीति को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि चुनावी रणनीति तय करने के लिए पार्टी 2८ सितंबर को विधायकों की बैठक करेगी। भाजपा भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। शुक्रवार

को भाजपा की बैठक के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। भाजपा के एक अन्य नेता ने कहा, "हम जल्द इस संबंध में फैसला लेंगे। हमारी पार्टी केंद्र आधारित है और सभी प्रमुख नेताओं से सलाह लेकर फैसले किए जाते हैं।" निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 90 सीट शामिल हैं, जिन पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 2५ नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए अधिसूचना 2६ सितंबर को जारी होगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर और मतगणना 9६ अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सदस्यों में भाजपा के अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बी.एल. वर्मा, सीमा द्विवेदी और हरदीप सिंह पुरी, सपा के रामगोपाल यादव तथा बहुजन समाज

पार्टी (बसपा) के रामजी गौतम शामिल हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की सीट 99 सितंबर से रिक्त है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनका इस्तीफा प्रभावी हुआ था। निवर्तमान 90 सीटों में से आठ भाजपा, एक सपा और एक बसपा के पास थीं। मौजूदा विधानसभा में



संख्या बल के आधार पर भाजपा को सर्वाधिक सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उसके बाद सपा का प्रतिनिधित्व होगा। हाल ही में आगरा की फतेहाबाद सीट से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन के बाद 803 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 2८८

विधायक हैं। इनमें भाजपा के 2५५, अपना दल (सोनेलाल) के 9३, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के नौ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के छह और निषाद पार्टी के पांच विधायक शामिल हैं। सपा-कांग्रेस गठबंधन के पास करीब 90३ विधायक हैं, जिनमें सपा के 909 विधायक शामिल हैं। जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो और तीन निर्दलीय विधायक हैं। इन तीन निर्दलीय विधायकों में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य मंत्री मनोज कुमार पांडेय भी शामिल हैं। ये तीनों विधायक सपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ गई थीं। विधान परिषद की 99 सीटों के लिए चुनाव 2३ अक्टूबर को होगा और मतगणना 2७ अक्टूबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन

क्षेत्रों के लिए अधिसूचना 2६ सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच सात अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्टूबर होगी। इन सीटों के लिए मतदान 2३ अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा और पूरी चुनाव प्रक्रिया ३9 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। संबंधित सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर को समाप्त हो रहा है। विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा के अवनीश कुमार सिंह, मानवेन्द्र प्रताप सिंह, दिनेश कुमार गोयल, उमेश द्विवेदी, श्रीचंद शर्मा और हरि सिंह दिल्लीय सपा के लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा और डॉ. मान सिंह यादव निर्दलीय आकाश अग्रवाल तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ध्रुव कुमार त्रिपाठी शामिल हैं।

सम्पादकीय

“निर्वाचन आयोग की नियुक्तिरू न्यायिक फैसले में देरी से बढ़ता अविश्वास”

मार्च २०२३ में सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। न्यायालय ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर होनी चाहिए। इस व्यवस्था का उद्देश्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत करना था, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव कराने वाली संस्था की स्वायत्तता का सीधा संबंध चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास से है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसी वर्ष दिसंबर में संसद के माध्यम से कानून बनाकर नियुक्ति समिति की संरचना बदल दी। नए प्रावधान के अनुसार समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया। इस बदलाव के साथ समिति में सत्ता पक्ष का बहुमत हो गया। कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और अब इस मामले में दो सदस्यीय पीठ का बंटा हुआ फैसला सामने आया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने याचिका में उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि नई व्यवस्था में नियुक्ति समिति के भीतर सत्ता पक्ष का बहुमत कायम हो जाता है और ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका प्रभावी भागीदारी के बजाय महज औपचारिक उपस्थिति तक सीमित हो सकती है। उन्होंने इस तर्क से भी सहमति जताई कि वर्तमान स्वरूप में नियुक्ति समिति को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा ने केंद्र की उस दलील से सहमति जताई कि इस मामले में महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिन पर बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप अब मामला फिर प्रधान न्यायाधीश के समक्ष है और वही तय करेंगे कि इस विषय पर संविधान पीठ गठित की जाए या नहीं। यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व व्यवस्था में बदलाव किए जाने के बाद करीब तीन वर्ष बीत चुके हैं। यदि अब संविधान पीठ गठित होती है तो सुनवाई और निर्णय में कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में समय लगना असामान्य नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रश्न सामान्य संवैधानिक विवादों जैसा नहीं है। इसका सीधा संबंध उस संस्था से है जो देश में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक चुनावों की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करती है। इस बीच कई चुनाव मौजूदा व्यवस्था के तहत नियुक्त निर्वाचन आयोग की देखरेख में हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसलिए इस विवाद का समाधान जितना लंबा खिंचेगा, उतना ही यह प्रश्न महत्वपूर्ण होता जाएगा कि चुनावी संस्था की नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक राजनीतिक सहमति और संस्थागत संतुलन कैसे सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन आयोग के प्रति सार्वजनिक विश्वास किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। हाल के वर्षों में आयोग की कार्यप्रणाली और निर्णयों को लेकर राजनीतिक दलों तथा नागरिक समाज की ओर से विभिन्न सवाल उठते रहे हैं। इन सवालों की वैधता पर अंतिम निर्णय संबंधित संस्थाओं और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए, लेकिन इतना स्पष्ट है कि चुनावी संस्था को लेकर पैदा होने वाला संदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ स्थिति नहीं है। इसलिए इस मामले में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि नियुक्ति संबंधी कानून संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। व्यापक प्रश्न यह भी है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर जनता का विश्वास कैसे कायम रखा जाए। न्यायपालिका को इस संवेदनशील प्रश्न पर अंतिम निर्णय देते समय संस्थागत स्वतंत्रता, सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन तथा चुनावी विश्वसनीयता जैसे सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। लोकतंत्र में चुनाव केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जनता के विश्वास का नाम भी है। इसलिए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े विवाद का समाधान अनिश्चितकाल तक टलते रहना उचित नहीं होगा। समयबद्ध न्यायिक निर्णय ही इस बहस को स्पष्ट दिशा दे सकता है और चुनावी संस्थाओं के प्रति विश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

यूपी बंटेगा तो राजभर का बेटा बनेगा सीएम: ओम प्रकाश राजभर के बयान से सियासी हलचल

लखनऊ। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसा बड़ा पद संभालने वाले सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हैं। यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और साल २०२७ का यूपी चुनाव भी योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनाने का एक अलग राग छेड़ दिया है। अब चाहे इसके लिए भले ही यूपी जैसे बड़े राज्य के चार टुकड़े हो जाए। मुख्यमंत्री तो राजभर का बेटा ही बनेगा। दरअसल जिस उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा काटकर अलग राज्य उत्तराखंड बना दिया गया उस उत्तर प्रदेश को एक बार फिर बांटने की चर्चाएं तेज होने लगी और इस बार सिर्फ एक हिस्से में नहीं यूपी को चार हिस्सों में बांटने की बात हो रही है और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि जब भी यूपी का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री राजभर का बेटा ही होगा। २४ साल से हम लोग इस बात को कहते आए हैं कि जिस दिन प्रदेश का बंटवारा होगा पश्चिम के लोग हरित प्रदेश की बात करते हैं। बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंड की बात करते हैं। पूर्वांचल के लोग पूर्वांचल की बात करते हैं। इसी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना रहा है। बिहार से झारखंड और छत्तीसगढ़ बना है। तो इतना बड़ा प्रदेश है। जब प्रदेश का बंटवारा होगा ५ साल लगे, १० साल लगे, २० साल लगे जब भी बंटवारा होगा तो उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री राजभर का बेटा होगा। ओम प्रकाश राजभर होंगे। अब हम कब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राजभर ने प्रदेश को बांटने में अड़चन का जिक्क करते हुए कहा कि एक सिस्टम है। सिस्टम में चल रहा है अपना काम। हमारी पार्टी का अपना मानना है। हम अपने जो मनिफेस्टो है उसमें हम अपने विचार लोगों की राय से पूर्वांचल के लोगों की राय से रखा गया है। जिस सुहेलदेव समाज पार्टी का अस्तित्व ही बीजेपी के दम पर है। उस पार्टी के अध्यक्ष राजभर यूपी के बंटवारे का सपना देख रहे हैं और यूपी का बंटवारा होते ही पूर्वांचल में राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं। वह भी ऐसे समय में जब कुछ ही महीनों बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त उन्हें राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान छोड़कर २०२७ में लगातार तीसरी बार योगी सरकार बनाने पर काम करना चाहिए था। लेकिन यूपी चुनाव से पहले ही वह राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चलाने लगे। जबकि अभी तो यूपी का बंटवारा भी नहीं हुआ है। यही वजह है कि उनके इस बयान पर योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने भी नसीहत देते हुए कहा कि हमें मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। वह जो भी फैसला लेंगे प्रदेश के हित में लेंगे। सभी को इस बात को मानना चाहिए और उसी आधार पर अपना बयान भी देना चाहिए। हम सब लोग लगातार ६० और ७० के दशक से यह बात सुन रहे हैं। जनता तो धैर्य के साथ सारे चीज का इंतजार कर रही है। मैं अपने सहयोगी दल के साथियों से भी मैं कहूंगा कि वह भी धैर्य बनाए रखें। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सामर्थ्यवान सरकार चल रही है। देश के हित में जो कुछ भी होगा और प्रदेश के हित में भी जो कुछ होगा वो हम सब लोगों को माननीय मोदी जी के ऊपर छोड़ना चाहिए। भारत के सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। हम सब लोग यह भी जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के बंटवारा करने का अधिकार देश की सरकार के पास है। माननीय मोदी जी के पास है। उनकी सरकार के पास है। तो हम सब लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मोदी जी का जो फैसला है वही प्रदेश के हित में भी है और देश के भी हित में है। सब लोगों को इस बात को मानना चाहिए। उसी आधार पर अपने बयान भी देने चाहिए और आगे भी चलना चाहिए। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का यह बयान बता रहा है कि बीजेपी को भी ओम प्रकाश राजभर का यह बयान रास नहीं आया क्योंकि उनका यही बयान अब योगी सरकार को भारी पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बहाने सपा नेता शिवपाल यादव ने तो सरकार पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि पहले बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म करिए। पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा। फिर दक्षिण भी दक्षिण भी बनेगा बुंदेलखंड बनेगा। फिर रोहिलखंड बनेगा। बनेगा पहले तो ये ये तो पहले ये तो विचार पहले करो। पूर्वांचल की बात तो तब करो पहले सब एक करो। कितने प्रदेश बनाओ। भाई एक कितने प्रदेश बनाओ? अखिलेश यादव ने भी राजभर के बयान के बहाने योगी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा जो देश के बंटवारे की बात कर रहे हैं वह राज्य के बंटवारे की भी बात कर रहे हैं। हमें अपने देश को ताकतवर बनाना है। कमजोर लोग ऐसी बातें करते हैं और कुछ लोग इनके साथ अंडरग्राउंड लेवल पर होंगे।

नहीं होगी बैंक की हड़ताल : आईबीए और यूएफबीयू की देर रात बैठक में बनी सहमति, टली बैंकों की महाहड़ताल!

लखनऊ। बैंक यूनियन ने पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करने समेत अपनी मांगों पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से मिले आश्वासन के बाद देशव्यापी तीन दिवसीय हड़ताल रविवार को स्थगित कर दी। सोमवार से शुरू होने वाली इस हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम अफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने किया था। यह हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र की छमाही लेखाबंदी के समय हो रही थी। हड़ताल स्थगित होने के बाद सोमवार को बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे। यूएफबीयू ने एक बयान में कहा, श्रृंखला की शनिवार को अवकाश घोषित करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए आईबीए और यूएफबीयू की एक उच्चस्तरीय समिति का तत्काल गठन किया जाएगा। यह समिति सभी संभावित विकल्पों पर विचार करेगी, सभी हितधारकों से चर्चा करेगी और ऐसा समाधान निकालने का प्रयास करेगी, जो सभी हितधारकों, खासकर ग्राहकों, को स्वीकार्य हो।” बयान में कहा गया कि स्केल-चार और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के संबंध में आईबीए के साथ बातचीत शुरू की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि इसके तहत यूनियन और संघों की आपत्तियों को दूर करने के लिए योजना में बदलाव का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। बयान में कहा गया कि आश्वासन के मद्देनजर यूएफबीयू ने प्रस्तावित आंदोलन और हड़ताल को स्थगित करने पर सहमति जताई।

MSME से मैनुफैक्चरिंग हब तक, ग्लोबल बाजार में यूपी की बढ़ती धमक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने न केवल MSME सेक्टर में तेजी से तरक्की की है, बल्कि एक नए मैनुफैक्चरिंग हब के तौर पर भी उभरा है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPIT) के चौथे एडिशन के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ट्रेड शो परंपरा और टेक्नोलॉजी, विरासत और इनोवेशन, और कारीगरी और बाजार की मिली-जुली ताकत को देखने और समझने का मौका देता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "UP ने न सिर्फ MSME सेक्टर में तेजी से तरक्की की है, बल्कि एक नए मैनुफैक्चरिंग हब के तौर पर भी उभरा है। पिछले साल इस ट्रेड शो में ७२ देशों के ५५० खरीदार शामिल हुए थे। यह संख्या बढ़कर ६० देशों के ६०० से ज्यादा खरीदारों तक पहुँच गई है और लगभग १,५०,००० B2B विजिटर्स के इस इवेंट का हिस्सा बनने की उम्मीद है। CM योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में अपना कामकाज शुरू करने और दुनिया भर में

एक्सपोर्ट करने का एक बेहतरीन जरिया बन रहा है। उन्होंने आगे कहा आज यहाँ कई देशों के अंतरराष्ट्रीय खरीदार मौजूद हैं यह साफ तौर पर दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों की



क्वालिटी, इसकी मजबूत सप्लाय चेन और यहाँ के उद्यमियों की विश्वसनीयता पर दुनिया को भरोसा है और यह सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है... आज 'नए भारत' में 'नए उत्तर प्रदेश' की अपार संभावनाओं को देखने का मौका है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UPIT) का चौथा एडिशन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहा है। यह एक्सपो २६ सितंबर को खत्म होगा। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड द्वारा

संयुक्त रूप से आयोजित इस इवेंट में २,४०० से ज्यादा एग्जिबिटर, १.५ लाख B2B खरीदार और विजिटर, ४.५ लाख आम विजिटर और ८५ देशों से ५५० से ज्यादा इंटरनेशनल खरीदार शामिल होंगे। इसका चौथा एडिशन राज्य की 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन कुजीन' (ODOC) पहल को, 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ODOP) पर पहले से मौजूद फोकस के साथ, काफी बढ़ावा देगा और उत्तर प्रदेश के आर्थिक इकोसिस्टम की व्यापकता को दिखाएगा। इस इवेंट में छह पार्टनर देश शामिल होंगे – ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम। अधिकारियों ने बताया कि ७२ देशों से विदेशी खरीदारों के रजिस्ट्रेशन मिले हैं और इवेंट से पहले रजिस्ट्रेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है। फेडरेशन अफ इंडियन एक्सपोर्ट अ गैनाइजेशन्स (FIEO) अपने शोस्टेड बायर प्रोग्राम के जरिए इंटरनेशनल खरीदारों तक पहुँचने में मदद कर रहा है, जो B2B मैचमेकिंग, नेटवर्किंग और बिजनेस सेशन तक पहुँच की सुविधा देगा।

सेवानिवृत्त पीसीएस अफसरों ने साझा किया दर्द, उठाई समस्याएं

लखनऊ। पीसीएस रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन की लखनऊ जनपद क्लस्टर बैठक रविवार को सेक्टर-१४, वृंदावन योजना में अवधेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भारी बारिश के बावजूद बैठक में ५३

की जानकारी दी। प्रांतीय महासचिव अमृतलाल साहू ने आठवें वेतन आयोग में पेंशनर्स को शामिल किए जाने की मांग तथा देशभर में कर्मचारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष और आंदोलनों की रणनीति पर विस्तार से प्रकाश



सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष टीएन द्विवेदी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे, जबकि संचालन प्रांतीय महासचिव अमृतलाल साहू ने किया। रामकुमार गौतम, जीत लाल सैनी और पीपी उपाध्याय संयुक्त संयोजक रहे। प्रांतीय अध्यक्ष टीएन द्विवेदी ने सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के नगदीकरण (कम्यूटेशन) के लिए होने वाली पेंशन कटौती की अवधि १५ वर्ष से घटाकर १२ वर्ष किए जाने से संबंधित प्रक्रिया और न्यायालयों में विचाराधीन मामलों

डाला। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष तेज करने पर जोर दिया। प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य रामकुमार गौतम ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक शहर और मोहल्ले में रहने वाले सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारियों की सूची तैयार कर उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखने का सुझाव दिया। उन्होंने आपसी मेल-जोल बढ़ाने और जरूरत के समय एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनने पर भी जोर दिया। प्रांतीय अध्यक्ष

ने संयुक्त पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित धरना-प्रदर्शनों में अधिक से अधिक सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में ओमप्रकाश गुप्ता, गंगाराम गुप्ता, त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, भगवान दीन वर्मा, सुरेश चंद शर्मा, वीरेंद्र बहादुर सिंह, अतुल प्रकाश श्रीवास्तव, महेश प्रकाश, सोबरन सिंह, विनय कुमार गुप्ता, जयप्रकाश यादव, अशोक कुमार शुक्ला, विद्या शंकर सिंह, शिव शंकर गुप्ता, तिलकधारी यादव, अनिल चतुर्वेदी, मोतीलाल यादव, राजकुमार, राकेश कुमार गुप्त, पारस मौर्य, भारत लाल सरोज, प्रेम प्रकाश उपाध्याय, देवेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेश कुमार गुप्ता, राम भरत तिवारी, राजेश चंद्र, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अंत में जीत लाल सैनी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में सेवानिवृत्ति के बाद आने वाली विभिन्न समस्याओं, मेडिकल रीइंबर्समेंट, न्यायालय में सरकार की ओर से साक्षी के रूप में उपस्थित होने पर पीएडिई के भुगतान तथा बीमारी की सूचना दिए जाने के बावजूद न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी होने जैसे मामलों पर चर्चा की गई।

योगी के दिल्ली दौरे से बढ़ी सियासी हलचल, मिशन २०२७ या राज्यसभा चुनाव की तैयारी?

लखनऊ। वैसे तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले बरस होने को है। लेकिन उससे पहले लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश से सत्ता की हैट्रिक लगाने को बेकरार प्रदेश की योगी सरकार ने दिल्ली दरबार में अपनी चहलकदमियां भी तेज कर दी हैं।



सूबे के मुखिया का दिल्ली दौरा राजनीतिक विश्लेषकों के ध्यान को आकर्षित कर रहा है। पहले तो सीएम योगी ने नोएडा में चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ शनिवार को भेंट वार्ता हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैठक दोपहर के वक्त करीब एक घंटे तक चली। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश से जुड़े विभिन्न अहम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई। जिनमें आने वाला विधानसभा और राज्यसभा चुनाव सबसे प्रमुख हैं। हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है। अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीव के साथ बैठक करेंगे। ऐसे में क्या ये मिशन २०२७ को लेकर मंथन का दौर है या फिर यूपी के १० राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले तैयारियों का खाका खींचा जा रहा है? उत्तर प्रदेश की १० राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। २०२७ के विधानसभा चुनाव से पहले इसे

एक अहम लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताजा दिल्ली दौरा महज प्रशासनिक नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भविष्य की राजनीतिक बिसात से जुड़ा देखा जा रहा है। संख्या बल के लिहाज से भाजपा गठबंधन के खाते में करीब ८ सीटें

जाती दिख रही हैं, लेकिन असली खींचतान नामों के चयन को लेकर है। पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका दिया जाए या फिर २०२७ के सियासी समीकरणों को धार देने के लिए नए चेहरों को संसद भेजा जाए। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए भाजपा ऐसे मजबूत नेताओं की तलाश में है जो जमीन पर अपने-अपने वर्गों में गहरी पैठ रखते हों। ओबीसी और दलित प्रतिनिधित्व के साथ-साथ सर्वर्ण (विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय) मतदाताओं की नाराजगी दूर करने और पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक का संतुलन साधना शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष रणनीतिकारों के साथ बैठक में टिकट वितरण के इसी फार्मूले को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। पार्टी की रणनीति साफ है। राज्यसभा के जरिए संगठन और सरकार में उन कड़ियों को मजबूत किया जाए जो आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का आधार बन सकें।

घर गेट गिरने से ७ वर्षीय मासूम की मौत

प्रतापगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र के सेनानी नगर मीराभवन मोहल्ले में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के घर पर किराए पर रह रहे एक ७ वर्षीय मासूम बच्चे की लोहे का गेट गिरने की वजह से मौत हो गई। मासूम की मौत से परिजन रो-रो कर बेहाल हैं। जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के मूल निवासी रजनीश शर्मा प्रतापगढ़ की एक कोल्ड ड्रिंक फ़ैक्ट्री में कर्मचारी हैं और वह अपने परिवार के साथ मीरा भवन मोहल्ले में स्थित भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के पैतृक आवास पर किराए पर रहते हैं। रविवार शाम

को उनका ७ वर्षीय बेटा आद्विक शर्मा घर के मुख्य गेट को पकड़कर झूल रहा था। इसी दौरान अचानक लोहे के गेट का एक हिस्सा टूटकर



सीधा मासूम अद्विक के ऊपर गिर पड़ा। गेट भारी होने के कारण मासूम उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद परिजन और आसपास के लोग आनन-फ़ानन में आद्विक को इलाज के लिए मेडिकल कलेज ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया।

घर घर जाकर इकट्ठा किए जाएंगे फॉर्म

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवाल और मनमाने तरीके से नाम काटे जाने के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की एक अहम बैठक शनिवार को हुई। आयोग की पूर्ण बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि जिनके नाम कटे हैं उनके फॉर्म इकट्ठा करने के लिए आयोग के लोग घर घर जाएंगे। शनिवार की बैठक में दिल्ली और महाराष्ट्र में एसआईआर से जुड़े दावे व आपत्तियां लेने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। शनिवार की बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि जिन लोगों के एसआईआर में नाम काटे गए हैं, उनके दावे और आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाई गई है। जिन लोगों को नाम मैप नहीं होने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी के

कारण नोटिस भेजा गया है, बीएलओ उनके घर जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करेंगे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इन पर रीजनल इलेक्टरल अफसर फैसला लेगा। इसके अलावा बैठक में नाइट शेल्टर में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए पर्याप्त हेल्प डेस्क या स्पेशल कैंप लगाए जाने का भी फैसला किया गया। गौरतलब है कि एसआईआर के दौरान अब तक ३० राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची से १३.३७ करोड़ नाम कम हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में कुल ६६.८८ करोड़ मतदाता हैं। इस लिहाज से करीब १४.१ फीसदी मतदाताओं के नाम एसआईआर में काटे गए। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की खबरों के बीच यह बैठक हुई। इस बैठक

में फैसला किया गया कि दिल्ली, महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख ३० अक्टूबर २०२६ तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली में विवाद का निपटारा ३० नवंबर और महाराष्ट्र में निपटारा १० नवंबर तक करना होगा। यह भी कहा गया कि गोवा में जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है, वहां ब्लॉक अफसर घर घर जाकर फर्म छह इकट्ठा करेंगे। गौरतलब है कि 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म छह में बिना सहमति के बदलाव करने की खबर दी गई है। इसे लेकर भी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। चुनाव आयोग ने शनिवार की बैठक के बाद कहा कि फॉर्म छह पर कोई विवाद है ही नहीं। फॉर्म छह को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

भारत का कबड्डी में ‘गोल्डन डबल’, पुरुष और महिला टीमों ने फाइनल में ईरान को हराया

नई दिल्ली। भारत ने एशियाई खेलों में पुरुष और महिला वर्ग में कबड्डी फाइनल में शनिवार को ईरान को हराकर दोहरी स्वर्णिम सफलता हासिल की। पुरुषों के रोमांचक मुकाबले में भारत ने ईरान को ४०-३४ से हराकर गोल्ड मेडल जीता और एशियाई खेलों में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया। महिला कबड्डी टीम ने ईरान को ३७-३४ से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम बरकरार रखा। पुरुष फाइनल में हाफ-टाइम तक भारत १८-१७ से पीछे था, लेकिन ब्रेक के बाद चुनौती का सामना करते हुए ईरान को 'अ ल-आउट' किया और मुकाबले पर पकड़ बनाते हुए कबड्डी में एशियाई खेलों का रिकर्ड नौवां गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत ने दूसरे हाफ में मैच का पासा पलट दिया है और ईरान को 'ऑल-आउट' करने के बाद बढ़त बना ली। मजबूत डिफेंस और स्मार्ट रेडिंग की मदद से भारत ने पिछड़ने के बाद वापसी की है और मैच के अंतिम चरणों में पाँच अंकों की बढ़त बना ली। कड़े मुक़बले वाले शुरुआती दौर के बाद, हाफ-टाइम तक ईरान की टीम भारत से १८-१७ से मामूली बढ़त बनाए हुए थी। ईरान ने इस दौरान मैच का एकमात्र 'ऑल-आउट' किया, लेकिन भारत ने हाफ का समापन मजबूती से किया और अंतर को घटाकर एक अंक कर दिया, जिससे वे मुक़बले में बने रहे। टोकाई सिटिजन्स जिम्नेजियम में हुए फाइनल मुकाबले में भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान को ३७-३४ से हराकर अपना एशियाई खेलों का चौथा स्वर्ण पदक जीता। अब तक हुए पांच एशियाई खेलों

में ईरान ने जकार्ता २०१८ में फाइनल में भारत को हराकर यह खिताब जीता था। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने फाइनल मैच की शुरुआत अपनी स्टार रेडर और कप्तान जहरा करीमी को बेंच पर बिठाकर की। डिफेंडिंग चौपियन ने शानदार शुरुआत की। रेडर पूजा, संजू देवी और निकिता हथवाला ने शुरुआती पॉइंट हासिल किए और टीम को ५-२ की बढ़त दिला दी। हालांकि, ईरान ने सुपर टैकल के जरिए स्कोर बराबर किया और ७-५ की बढ़त बना ली। लेकिन भारत ने तुरंत वापसी की और मैच का पहला 'अ ल आउट' करके ईरान पर १३-१०



की बढ़त बना ली। इसके तुरंत बाद निकिता हथवाला ने दो पइंट की रेड की और स्कोर १५-१० कर दिया। मैट पर वापस लौटी करीमी ने अतेना मादेदी की मदद से मैच का रुख पलटने की कोशिश की। हालांकि, भारतीय डिफेंस ने ईरान की स्टार रेडर सानिया नईमी को कोई मौका नहीं दिया और उन पर पूरी तरह काबू बनाए रखा। संजू देवी ने एक और मल्टी-पॉइंट रेड की जिसमें बोनस और दो टच पॉइंट शामिल थे जबकि डिफेंस ने लगातार सफल टैकल किए। इससे हाफ-टाइम से दो मिनट पहले ही भारत की बढ़त दहाई के अंक (डबल डिजिट) तक पहुंच गई। हाफ-टाइम की सीटी बजने

से पहले के आखिरी दो मिनट ईरान के नाम रहे। एक सुपर टैकल, उसके बाद बोनस और मादेदी के शानदार एंकल होल्ड की बदौलत जकार्ता २०१८ की चौपियन टीम ने ब्रेक तक अंतर को कम करके २२-१६ कर दिया। दूसरे हाफ में ईरान पूरी तरह जोश में नजर आया। डिफेंस के मजबूत खेल और सानिया नईमी के अचानक लय में आने से, उन्होंने स्कोर का अंतर कम करके २३-२० कर दिया। दबाव के बीच, जब मैट पर भारत की सिर्फ दो खिलाड़ी बची थीं, रितु नेगी ने सानिया को 'थाई होल्ड' करके शानदार सुपर टैकल किया। पूजा ने भी अहम पॉइंट हासिल किए ताकि भारत 'ऑल आउट' न हो जाए। लेकिन आखिरकार मदादी ने एक ही रेड में दो टच पॉइंट हासिल करके भारत को 'अ ल आउट' कर दिया और खेल खत्म होने में आठ मिनट बाकी रहते हुए स्कोर को सिर्फ एक पॉइंट (२७-२६) के अंतर पर ला दिया। मैच का रुख बदलने के लिए भारत ने रेडर्स पर भरोसा जताया और उन्होंने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। पूजा ने पूरे मैच की तरह टच पइंट हासिल करना जारी रखा और संजू देवी ने भी कुछ बड़ी रेड्स के जरिए योगदान दिया। खेल खत्म होने में चार मिनट से कुछ ज्यादा समय बचा था और भारत ने ३४-२८ की बढ़त बना ली थी। जैसे-जैसे समय बीतता गया, ईरान के खेल में गलतियाँ होती गईं, जबकि भारत ने रेड्स के दौरान समय बिताने की कोशिश की। आखिरकार भारत ने ३७-३४ से जीत हासिल की और अपना खिताब बचाए रखा।

कबड्डी में भारत ने दो गोल्ड जीते

नई दिल्ली। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत ने तीन स्थानों की छलांग लगाई है। शनिवार को खेल के सातवें दिन भारत को कबड्डी में दो गोल्ड मिले, जिसके बाद भारत के कुल गोल्ड मेडल की संख्या चार हो गई। भारत कुल ३० पदकों के साथ पदक तालिका में १०वें स्थान पर है। भारत को चार गोल्ड



के अलावा १२ सिल्वर और १४ ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। बहरहाल, शनिवार का दिन भारत की कबड्डी टीम के नाम रहा। एशियाई खेलों में भारत ने कबड्डी के दोनों गोल्ड जीत लिए। महिला टीम ने ईरान को ३७-३४ और पुरुष टीम ने भी ईरान को ४०-३४ से हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष टीम ने लगातार १०वीं बार और महिला टीम ने लगातार पांचवें एशियाड में मेडल जीता। एथलेटिक्स में तजिंदरपाल सिंह तूर ने शॉटपुट में २०.६४ मीटर के

थ्रो के साथ सिल्वर जीता। प्राची चौधरी ने चार सौ मीटर में ५३.२१ सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया। भारत को मैराथन और शूटिंग में भी सिल्वर मिले। शनिवार को स्कव्श में अनाहत सिंह और अभय सिंह फाइनल में पहुंचे। भारत के लिए स्कवॉश में भी ऐतिहासिक दिन रहा। १८ साल की अनाहत सिंह

और अभय सिंह ने सिंगल्स के फाइनल में जगह बनाई। एशियन गेम्स में पहली बार भारत के दो खिलाड़ी पुरुष और महिला सिंगल्स के फाइनल तक पहुंचे हैं। एथलेटिक्स में सावन बरवाल ने पुरुष मैराथन में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने दो घंटे ११ मिनट ३७ सेकंड में रेस पूरी की और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एशियन गेम्स की पुरुष मैराथन में भारत को ४४ साल बाद मेडल मिला है। साथ ही पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई।

नेहा बोरा जंतर मंतर पहुंची, सीजेपी का प्रदर्शन टला

नई दिल्ली। कॉंग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी ने पहले तो ४८ घंटे का अल्टीमेटम दिया था लेकिन अब उसे आगे बढ़ा दिया गया है। सीजेपी के नेताओं ने कहा है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो सीजेपी दो अक्टूबर से देश भर में प्रदर्शन करेगी। पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने के लिए ४८ घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच शुक्रवार को

सीपीआई माले की छात्र ईकाई आईसा की नेहा बोरा जंतर मंतर पहुंच गई। हालांकि उनके प्रदर्शन के ऐलान के बाद जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। बैरिकेड्स के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बसों में भर कर ले गई। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी वहां मौजूद थे। उन्हें और मशहूर वकील प्रशांत भूषण को पुलिस ने हिरासत में लिया।

ईरान युद्ध में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर ८६१ हुई

नई दिल्ली। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ईरान संघर्ष के लिए अपने सार्वजनिक घायलों के डेटाबेस में ३७ और घायल सैन्य कर्मियों, २६ नाविकों और आठ मरीन, को शामिल किया है, जिससे कुल संख्या बढ़कर ८६१ हो गई है। यह जानकारी व शिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से प्राप्त हुई। पेंटागन अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि नई सूची में शामिल लोग कब या कैसे घायल हुए। हताहतों की बढ़ती संख्या ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और इजरायल का

महीनों से चल रहा अभियान ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने या अमेरिका द्वारा तय किए गए युद्ध के किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, यह युद्ध एक ऐसे गतिरोध में बदल गया है जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि ईरान सत्ता में बना हुआ है, अमेरिका के दबाव का विरोध कर रहा है और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना मजबूत नियंत्रण बनाए हुए है। फिर भी, ट्रंप प्रशासन ने इस संघर्ष को खत्म करने के बजाय इसे जारी रखा है।

ज्ञानेश के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार, २५ सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सभी राज्यों की राजधानी में शुक्रवार को मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। गौरतलब है कि एक दिन पहले गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी करने का आरोप दोहराया था और उनको देशद्रोही कहा था। इसके बाद ही कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन का फैसला किया। कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को सभी राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन किया तो सोमवार को सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के नेता कलेक्टर कार्यालय तक मार्च करेंगे। शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस ने पानी की बौछार मार कर उनको तितर बितर किया। पटना में राष्ट्रीय जनता दल ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया

और उनका पुतला जलाया। गौरतलब है कि अंग्रेजी के अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त मनमाने तरीके से आयोग चला रहे हैं और बाकी दो आयुक्तों को किसी भी फैसले में



शामिल नहीं किया जा रहा है। मतदाताओं के नाम काटने और जोड़ने से लेकर कई तरह की गड़बड़ियों के आरोप उस रिपोर्ट में लगाए गए हैं। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ज्ञानेश कुमार और केंद्र सरकार पर हमलावर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले १० महीनों में १४ बार दोनों चुनाव आयुक्तों ने आयोग के फैसलों पर आपत्ति जताई है। बहरहाल, शुक्रवार को पटना से लेकर बंगलुरु और श्रीनगर से लेकर

लखनऊ तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की और उनको हटाने की मांग की। कांग्रेस विधायक पोस्टर लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। छत्तसीगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरे। मतदाता सूची में बदलाव और एसआईआर के जरिए कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक से शास्त्री चौक स्थित मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया।

पाक पीएम को भारत ने दिया जवाब

नई दिल्ली। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की सालाना बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और साथ ही भारत में इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि भारत में मस्जिदों पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने का भी जिक्र किया। शहबाज ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए उसे गले की नस बताया। हालांकि जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने वहीं उनके सभी आरोपों का जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अधिकारी पेटल गहलोत ने पाकिस्तानी पीएम को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को नीति

के तौर पर अमल में लाता है। उन्होंने पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं को कठपुतली बताते हुए कहा कि पाकिस्तान का शासन 'सेना का, सेना द्वारा, सेना के लिए है'। उन्होंने कहा कि कठपुतलियां आती जाती हैं। पेटल गहलोत ने पीओके की घटनाओं की याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने लोगों पर किस तरह से जुल्म करता है यह देखना चाहिए। इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाक पीएम ने भारत को जंग की धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत सिंधु नदी का पानी न रोके। पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तान युद्ध की कार्रवाई मानेगा। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर उनके लिए गर्दन की नस है। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में पहलगाम हमले के बाद

हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान की सेना ने फील्ड मार्शल आसीम मुनीर के नेतृत्व में सटीक जवाब दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि मई २०२५ में दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने और युद्ध जैसी स्थिति टालने में उनकी भूमिका अहम रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को नफरत भरी बयानबाजी, भेदभाव और हमलों का सामना करना पड़ रहा है। मस्जिदों पर हमले और कुरान के अपमान की घटनाएं भी चिंता का विषय हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने का आरोप लगाया।

एयर इंडिया के पायलट को स्विट्जरलैंड में उतारा गया

नई दिल्ली। एयर इंडिया का एक और पायलट नशे में पाया गया है। नशे में होने की वजह से उसे स्विट्जरलैंड में ही जहाज से उतार लिया गया। एयर इंडिया की यह उड़ान ज्यूरिख से नई दिल्ली की थी। उड़ान से पहले होने वाले अनिवार्य अल्कोहल टेस्ट में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद एयर इंडिया ने पायलट को स्विट्जरलैंड में उतार दिया और उसे निलंबित कर दिया। जांच पूरी होने तक पायलट का निलंबन जारी रहेगा। बताया गया है कि यह मामला छह सितंबर का है। खबरों के मुताबिक विमान के टेकअफ से

पहले ग्राउंड स्टाफ को पायलट से शराब की गंध आई थी। उन्होंने अधिकारियों को उसकी सूचना दी, जिसके बाद पायलट को विमान से उतार दिया गया। उसे उसी



फ्लाइट से भारत भेजा गया था। स्विस फेडरल अफिस अफ सिविल एविएशन ने इस मामले की पुष्टि की है। उसके मुताबिक, पायलट पर स्विस नियमों के तहत कार्रवाई की गई और इसकी

जानकारी भारत के विमानन निदेशालय को दी गई। एयर इंडिया में पायलटों से जुड़े नियमों के उल्लंघन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही उड़ान के कमांडर पायलट का ड्रग टेस्ट दो बार पॉजिटिव आया था। गौरतलब है कि फुकेट से दिल्ली की फ्लाइट अचानक तीन सौ फीट नीचे आ गई थी। विमान में १४ लोग सवार थे। इनमें २० से ज्यादा यात्री और चालक दल के चार सदस्य घायल हुए थे। बाद में जांच में पायलट के नशीले पदार्थ का सेवन करने की पुष्टि हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट और बॉम्ब हाई कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मनमाने तरीके से चुनाव आयोग को चलाने के 'इंडियन एक्सप्रेस' के खुलासे के बाद अब मामला अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर की है तो दो याचिकाएं बम्बे हाई कोर्ट में दर्ज की गई हैं। दोनों अदालतों में दायर याचिकाओं में एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द करने और मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने के काम में ज्यादा पारदर्शिता लाने का निर्देश देने की अपील की गई है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट में दर्ज दो याचिकाओं में महाराष्ट्र की एसआईआर का विरोध किया गया है। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। अखबार की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं का दावा है कि दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर से जुड़े कई आदेश



जारी किए। दोनों याचिकाओं में इन आदेशों को रद्द करने और चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए फैसलों, जारी दिशा निर्देशों और साफ्टवेयर में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई सामूहिक निर्णय लेने की वैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन करती है। यह याचिका अधिवक्ता चांद कुरैशी के जरिए अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए फैसलों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जाए।

भाजपा की दो सहयोगी पार्टियों ने उठाए सवाल

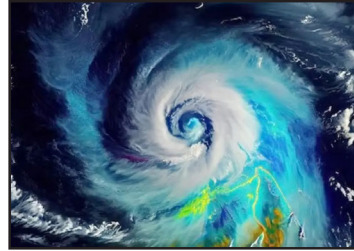
नई दिल्ली। देश की विपक्षी पार्टियां तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर हमला कर ही रही हैं अब दो सहयोगी पार्टियों ने भी सवाल उठाए हैं। बिहार की दो सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग से ज्यादा स्पष्टता से अपनी बात रखने को कहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले यह बात कही और उसके बाद राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी यह मुद्दा उठाया। चिराग पासवान ने कहा कि वे सरकार का हिस्सा हैं साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी संवैधानिक संस्था का बचाव नहीं करना चाहते। चिराग ने कहा कि अगर जनता का चुनावी व्यवस्था से भरोसा उठने लगा तो यह

लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, 'चुनाव आयोग को अधिक मजबूती से अपना स्पष्टीकरण जनता के सामने रखना चाहिए। जनता के मन में जो शंकाएं पैदा हुई हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए'। इसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'एसआईआर पर उत्पन्न विवाद से जनता में काफी उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। इस विषय को एड्रेस करने की जरूरत है। कंप्यूजन दूर करने हेतु चुनाव आयोग द्वारा अविलंब सही स्थिति पर स्पष्टीकरण आना चाहिए'।

चक्रवात अर्नब के कारण ४८ घंटे से बारिश

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अर्नब के असर से देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के साथ साथ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। कई जगह तो ४८ घंटे से बारिश हो रही है। बारिश के साथ कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में उत्तर प्रदेश में १६ लोगों की मौत हो चुकी है। चक्रवात अर्नब के असर से उत्तर प्रदेश, बिहार सहित आठ राज्यों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते राजस्थान व मध्य प्रदेश सहित १४ राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में

करीब ४८ घंटे से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के ३२ जिलों में बाढ़ का खतरा है। बिहार में सुपौल के ५० गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। १६ जिलों में यलो अलर्ट है। बारिश से



जुड़ी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हुई है। उधर उत्तराखंड में चमोली के हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ में शनिवार को बर्फबारी हुई। वहीं, पिथौरागढ़ सड़क पर भूस्खलन के चलते तीन सौ से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं। चारधाम यात्रा दो दिनों के लिए रोक दी गई है।

SIR पर सियासत गरम, योगी बोले-संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाओं और ईवीएम को लेकर सवाल उठाने पर निशाना साधा। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष की आपत्तियों पर भी बात की। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, “कांग्रेस और विपक्षी दलों का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है कि वे अपने राजनीतिक हितों के लिए भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की हर साजिश का हिस्सा बनते रहे हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नुकसान पहुंच सकता है।” उन्होंने कहा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से जुड़े अन्य दलों के मौजूदा काम और बयान “बेहद गैर-जिम्मेदाराना” हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए

जा रहे सवालों पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा कि मौजूदा चुनाव आयोग ऐसी प्रक्रिया कराने वाला पहला आयोग है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी, अक्सर कांग्रेस की सरकारों के समय, १९५२, १९५७, १९६१, १९६५-६६ और २००३ में ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं।



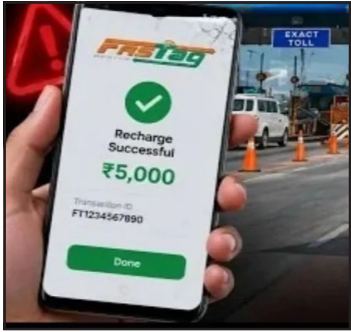
उनके मुताबिक, इस इतिहास के बावजूद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और दूसरी पार्टियों का मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हंगामा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा, “अगर वे चुनाव जीतती हैं, तो इसका श्रेय वे अपनी कोशिशों को देती हैं, लेकिन अगर जनता उन्हें उनके भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ियों, गलत नीतियों और अराजक कामों की वजह से नकार देती है, तो चुनाव आयोग

या ईवीएम को दोष देना कितना सही है?” उन्होंने विपक्षी दलों से इस पर सोचने और आत्म-मंथन करने की बात कही। योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर शक करने की कोशिश करता है और चुनाव आयोग पर हमला कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भारत की न्यायपालिका पर सवाल उठाए और भारतीय न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर शक करने की कोशिश की। उन्होंने २०१६ में राफेल मामले पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की टिप्पणियों को लेकर उठाए गए सवालों का भी जिक्र किया। ईवीएम के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्हीं मशीनों के जरिए केंद्र और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनीं। उन्होंने कहा कि इन ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहना और इस तरह भारत की चुनावी व्यवस्था तथा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर शक करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

फर्जी फास्टैग से ५ करोड़ की टोल टैक्स चोरी, १४२ गाड़ियों का खुलासाय एसटीएफ जांच में जुटी

लखनऊ। प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों और गलत गाड़ी नंबरों के सहारे टोल टैक्स चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी फास्टैग बनाकर टोल प्लाजा से गाड़ियां निकालने के इस खेल में अब तक सरकारी खजाने को ५ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंच चुका है। जांच में सामने आया है कि १४२ से ज्यादा गाड़ियां फर्जी नंबर और कूटरचित कागजातों के दम पर टोल पार कर रही थीं। अधिकारियों का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है, जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, घोटाले का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच स्पेशल

टार्स्क फोर्स (STF) को सौंपी गई है। STF ने कार्रवाई करते हुए टोल प्लाजा पर छापेमारी की



और वहां से डीवीआर, सर्वर और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। जांच टीम अब पूरे सिस्टम को खंगाल रही है ताकि इस फर्जीवाड़े की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। जांच एजेंसियों को अंदेशा

है कि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आ रही है। इसी वजह से एसटीएफ की एक विशेषज्ञ टीम अब सर्वर और डीवीआर से पुराना डाटा रिकवर करने में लगी हुई है। डिजिटल डाटा और डिलीट हुई फुटेज रिकवर होते ही यह साफ हो जाएगा कि फर्जी नंबरों वाली गाड़ियां कब-कब और कितनी बार टोल प्लाजा से गुजरीं। इसके बाद इस पूरे रैकेट के पीछे छिपे मास्टरमाइंड और टोल कर्मचारियों की मिलीभगत का भी पर्दाफाश हो जाएगा।

फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही खाते से ११ हजार पार, साइबर ठगों ने महिला को बनाया शिकार

लखनऊ। राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में साइबर जालसाजों ने एक महिला को अपनी ठगी का शिकार बना लिया। शातिर ठगों ने झांसा देकर महिला के बैंक खाते से किश्तों में ६६ हजार १०० रुपये पार कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर पारा पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दौदा खेड़ा (मानक

नगर) की निवासी शालनी भारती का एसबीआई (आरडीएसओ शाखा) में खाता है। पीड़िता के मुताबिक, उनके पति संतोष कुमार सिंह के एक छात्र के पिता के मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया था। इसमें एक ऐप का लिंक था और मदद की गुहार लगाई गई थी। पीड़िता ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, उनके खाते से पैसे कटने के मैसेज आने लगे।

देखते ही देखते ठगों ने ६६,१०० रुपये साफ कर दिए। मैसेज देखकर परिजनों के होश उड़ गए। ठगी का अहसास होते ही पीड़िता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पारा थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उन खातों की पड़ताल कर रही है जिनमें रकम ट्रांसफर हुई है।

रायबरेली पहुंची अखिलेश यादव की “PDA रथ” यात्रा, कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम जुटा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के PDA रथ के काफिले को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ के कारण कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लाल समाजवादी टोपी पहने समर्थकों ने जोश के

कार्यकर्ताओं के साथ लाल रंग की प्रचार बसें गुरुवार को लखनऊ से रवाना हुईं। ‘PDA रथ’ का यह दौरा मध्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की व्यापक लामबंदी कोशिशों का हिस्सा है। २०२७ के चुनावों से पहले पार्टी का ध्यान पिछड़े, दलित और



साथ पार्टी के झंडे लहराए और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। यादव अपनी प्रचार बस के खुले हिस्से में खड़े होकर भीड़ का अभिवादन कर रहे थे और हाईवे पर कई सौ मीटर तक जमा हुए समर्थकों के उत्साहपूर्ण नारों का जवाब दे रहे थे। रायबरेली में लोगों की यह भारी भीड़ – जो गांधी परिवार का गढ़ है और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय सीट है – समाजवादी पार्टी के लिए ताकत के एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है। बछरावां इलाके के चुरुआ गांव में यादव के ‘PDA रथ’ पर सवार होने के साथ ही उनके स्वागत का कार्यक्रम हुआ, जिससे २०२७ के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए उनके प्रचार अभियान की आधिकारिक शुरुआत हुई। पार्टी

अल्पसंख्यक समुदायों के गठबंधन पर है। २०२७ के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत, यादव ने हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के वोटों की संख्या २७,००० बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, उन्होंने पार्टी की रणनीति बताई, राज्य की कानून-व्यवस्था के प्रबंधन की आलोचना की, और मुस्लिम समुदाय का धन्यवाद करते हुए बीजेपी और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि २०२७ के विधानसभा चुनावों में हम हर विधानसभा सीट पर २७,००० वोट बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसका मतलब है कि हम बीजेपी के २७,००० वोट कम करेंगे, जिससे पार्टी के चुनावी नजरिए का संकेत मिलता है।

आंधी-बारिश में उखड़े ७ बिजली खंभे, ट्रांसफार्मर गिराय २०० घरों की बत्ती

गुल, पावर हाउस पर हंगामा

लखनऊ, सरोजनीनगर के अमौसी स्थित साई सुरक्षा नगर में शनिवार दोपहर आई बारिश और तेज आंधी के कारण बड़ा हादसा होते-होते बचा। ११,००० वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन पर एक पेड़ की डाल गिर जाने से डबल पोल पर रखा विद्युत ट्रांसफार्मर और लाइन के ७ खंभे उखड़कर जमीन पर आ गिरे। हादसे के बाद से करीब २०० घरों की बत्ती गुल



है और सड़क पर फैले तारों से राहगीरों की जान पर खतरा बना हुआ है। अधिकारियों की बेपरवाही से नाराज होकर दर्जनों उपभोक्ता रविवार सुबह करीब १० बजे नादरगंज पावर हाउस पहुंचे और जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका नादरगंज पावर हाउस के गौरी फीडर से जुड़ा है। शनिवार दोपहर करीब ३ बजे हादसा होने के तुरंत

बाद पावर हाउस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन विभाग ने कोई सुध नहीं ली। सूचना के नाम पर सिर्फ दो बिजलीकर्मि आए और मुआयना करके लौट गए। पूरी रात बिजली न रहने से घरों के समरसेबल बंद रहे, जिससे इलाके में पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। अधिकारियों के रवैये से तंग आकर रविवार सुबह लोगों का सब्र टूट गया और वे नादरगंज पावर हाउस पर जुट गए। पावर हाउस पर उपभोक्ताओं के भारी हंगामे को देखकर वहां मौजूद अवर अभियंता (श्रम) दिनकर यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने उग्र उपभोक्ताओं को समझाया और जल्द से जल्द नए खंभे लगवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल करने का लिखित व मौखिक आश्वासन दिया। इसके बाद ही नाराज लोग शांत होकर वापस लौटे।

देवीपाटन मंडल के एक लाख बच्चों को मिली फोल्डिंग स्टडी टेबल, पढ़ाई के लिए मिलेगी बेहतर सुविधा

लखनऊ। गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर देवीपाटन मंडल के एक लाख बच्चों को फोल्डिंग स्टडी टेबल वितरित की गई हैं। इसका लाभ गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के बच्चों को मिला है। स्टडी टेबल मिलने से बच्चों को घर पर किताब-क पी रखने और बैठकर पढ़ाई करने के लिए सुविधाजनक जगह मिल सकेगी। सरकार की इस पहल से बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला। कई बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम कार्ड और पत्र भेजकर उनका आभार जताया। बच्चों ने अपने संदेश में पढ़ाई में मदद के लिए मुख्यमंत्री

को धन्यवाद दिया और 'थैंक्यू' कहा। यह पहल खास तौर पर उन बच्चों को ध्यान में रखकर की गई है, जिन्हें घर पर पढ़ाई के लिए उचित सुविधा नहीं मिल



पाती। फोल्डिंग टेबल के जरिए ऐसे बच्चों को किताब-क पी रखने के साथ पढ़ाई के लिए बेहतर जगह उपलब्ध हो सकेगी। मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के अनुसार, अभियान के तहत सबसे अधिक ३४,२६० स्टडी टेबल बहराइच में वितरित की गई। इसके

बाद गोंडा में २७,६५०, बलरामपुर में २६,६८४ और श्रावस्ती में ११,१०६ टेबल दी गई। इस तरह देवीपाटन मंडल ने एक लाख स्टडी टेबल वितरण का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया। मंडलायुक्त के मुताबिक, 'शिक्षा की उड़ान' अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्टडी टेबल देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सभी छात्राओं को भी लाभार्थियों में शामिल किया गया है। अभियान को सतत रूप से संचालित करने की योजना है, ताकि भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्राइवेट बस यूनियन के चक्का जाम पर हड़कंप सड़क पर उतरे आरटीओ खीरी।

पलियाकलां—खीरी। पलिया के क्षेत्रों में टैक्सी अ टो ई रिक्षा के खिलाफ पलिया बस यूनियन ने २८ सितम्बर को अनिश्चितकालीन हड़ताल का जैसे ही बैठक कर

फ र म । न सुनाया या यह बात आगे की त र ह ल खी म पुर जिले तक पहुंच गई और ल खी म पुर खीरी जिले के प रिवहन



विभाग में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आरटीओ विभाग ने क्षेत्र में दौरा कर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। रविवार की सुबह जैसे ही परिवहन विभाग के अधिकारी की गाड़ी पलिया में लिखाई दी सड़कों पर अवैध तरीके से फर्माटा भर

रही डग्गामार वाहन गायब हो गए यही नहीं कई जगह बनाए हुए स्टैंड भी खाली नजर आए। वही जैसे ही या काफिला थाना संपूर्णनगर के फैक्ट्री तिराहे पर

पहुंचा वहां भी सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देने लगा। क्षेत्र में जैसे-जैसे कार्रवाई के लिए आरटीओ के अधिकारी जहां जहां पहुंचते गए सभी डग्गामार वाहन पहले ही सतर्क होकर गायब हो गए।

निघासन में बाढ़ का खतरा बढ़ा, मोहाना नदी उफान पर



लखीमपुर खीरी में लगातार तीन दिनों की भारी बारिश के बाद निघासन तहसील क्षेत्र में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। ब र्डर पर मोहाना नदी उफान पर है, वहीं शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। एसडीएम

गरीबी में बीमारी ने तोड़ी परिवार की कमर रोटी को मोहताज हुआ परिवार न राशन कार्ड, न आयुष्मानय छह बच्चों के सामने संकट

गोला गोकर्णनाथ खीरी। बांकेगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत संसारपुर के ग्राम विलाहिया से गंभीर बीमारी और बदहाली से जूझ रहे एक गरीब परिवार की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। गांव निवासी घनश्याम पुत्र रामस्वरूप पिछले करीब दो महीनों से पैरालिसिस (लकवा) की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के कारण वह न चल-फिर पा रहे हैं और न ही बोलने की स्थिति में हैं। वह पूरी तरह बिस्तर पर लाचार हैं। घनश्याम परिवार में अकेले कमाने वाले थे। उनके बीमार होने के बाद पत्नी और चार बेटियों व दो छोटे बेटों समेत छह बच्चों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परिजनों के मुताबिक शुरुआती इलाज में घर का बचा-कुचा सामान और जमा-पूंजी तक बिक चुकी है। परिवार कच्चे मकान में किसी तरह गुजर-बसर कर रहा है। परिवार के पास न राशन कार्ड है और न आयुष्मान भारत कार्ड। राशन कार्ड के अभाव में सरकारी खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि आयुष्मान कार्ड न

होने और आर्थिक तंगी के कारण घनश्याम का बेहतर अस्पताल में इलाज कराना परिवार के लिए मुश्किल है। मामले में संबंधित जिम्मेदारों से संपर्क कर उनका पक्ष लिया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक अवरस्थी ने बताया कि उन्हें यहां आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आज ही मामले की जानकारी हुई है। वह पूरी जानकारी कर जांच करेंगे तथा शासन की ओर से संभव मदद की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामप्रसाद देवल ने बताया कि राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड न होने की जानकारी उन्हें नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में घनश्याम का नाम डलवा दिया गया है। सरकार से आवास स्वीत होने पर उन्हें आवास दिलाया जाएगा। परिजनों और ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से तत्काल राशन और घनश्याम के निशुल्क समुचित उपचार की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को राहत मिल सके।

शटडाउन में लापरवाही से गई संविदाकर्मी की जान, ११ हजार वोल्ट की लाइन पर करंट लगने से मौत

लखनऊ, चिनहट डिविजन स्थित ओमेगा (UPSIDC) उपकेंद्र पर रविवार दोपहर करीब १२ बजे एक दर्दनाक हादसे ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। ११ हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन में आए फ ल्ट को ठीक करने खंभे पर चढ़े बाराबंकी निवासी ३५ वर्षीय अकुशल संविदा कर्मी रंजीत रावत करंट का तेज झटका लगते ही नीचे आ गिरे और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के वहां हड़कंप मच गया और मौके पर बीबीडी पुलिस को सूचना दी गई। चिनहट के अधिशासी अभियंता अभय कुमार सिंह ने बताया कि रविवार दोपहर संविदा कर्मी जिस लाइन पर काम कर रहा था, उसका शटडाउन न लेकर किसी अन्य लाइन का शटडाउन ले लिया गया था, जिससे यह भीषण हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि १६१२ या JE/SDO स्तर पर कोई आधिकारिक ब्रेकडाउन दर्ज नहीं था। घटना की सूचना के बाद बीबीडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे

में लिया, पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम, मृत्यु प्रमाण पत्र और वारिसान दस्तावेज पूरे होने के बाद नियमानुसार परिवार को मुआवजा दिया जाएगा।



आउटसोर्सिंग एजेंसी 'क्वेस्ट कॉर्पोरेशन' के तहत काम करने वाले रंजीत अपने पीछे बिलखती पत्नी और दो छोटे-छोटे मासूम बच्चों (१२ वर्ष और ६ वर्ष) को छोड़ गए हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी रंजीत के ही कंधों पर थी। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है। पिछले २-३ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच रंजीत भी मुस्तैदी से बिजली आपूर्ति बहाल करने की जंग में जुटे हुए थे, लेकिन किसे पता था

कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पांडे ने घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अकुशल कर्मचारियों से पोल या लाइन का खतरनाक काम न लिया जाए। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर अकुशल कर्मियों से १२ से १६ घंटे तक जबरन काम कराया जा रहा है और उन्हें सुरक्षा उपकरण तक मुहैया नहीं कराए जाते। हादसे के बाद से स्थानीय अधिकारी मामले पर पर्दा डालने और फोन उठाने से बच रहे हैं। देवेन्द्र कुमार पांडे ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर मृतक से पहले भी बिना सुरक्षा नियमों के काम लिया जा रहा था, तो संबंधित जेई, एसडीओ और एक्सियन के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

मूसलाधार वर्षा एवं जलसंकट में पालिका बनी संकटमोचक, टैंकरों से मिली राहत

लखीमपुर-खीरी। मूसलाधार वर्षा एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न जलभराव के कारण नगर के विभिन्न मोहल्लों में पेयजल संकट गहरा गया था। ऐसे विषम परिस्थिति में नगर पालिका परिषद लखीमपुर ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए सराहनीय पहल की। पालिका प्रशासन द्वारा गोटेट्या बाग, नई बस्ती, रानीगंज, शिव क लोनी, काशीनगर, थरबरगंज स्थित

जीजीआईसी विद्यालय के समीप एवं रामनगर क लोनी सहित जलप्लावित समस्त वार्डों में पेयजल टैंकरों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गई, जिससे नगरवासियों ने राहत की सांस ली। अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अनवरत वर्षा एवं विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण नलकूपों का संचालन ठप हो गया था, जिससे पेयजल वितरण व्यवस्था चरमरा गई थी।

स्थिति की विकटता को देखते हुए पालिका ने युद्धस्तर पर पेयजल टैंकरों की व्यवस्था की। पालिका की टीमों प्रत्येक वार्ड में सतत निगरानी कर रही हैं। जहां पेयजल समस्या है, वहां तत्क्षण टैंकर प्रेषित किया जा रहा है। पालिका की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्यप्रणाली से नगरवासियों में हर्ष व्याप्त है तथा लोग पालिका प्रशासन की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के उत्पादों पर बढ़ा दुनिया का भरोसा, निर्यात दो लाख करोड़ के पार: योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों की गुणवत्ता, मजबूत सप्लाय चेन और उद्यमियों की विश्वसनीयता पर आज पूरी दुनिया को भरोसा है। प्रदेश दो



लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा है। योगी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। इस बार ६० देशों से ६०० से अधिक विदेशी खरीदार और २४०० से अधिक एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। दोनों नेताओं ने एक ही ई-कार्ट से ट्रेड शो का अवलोकन किया और उद्यमियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अपनी जड़ों से जुड़कर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, दुनिया उसे फ लो करती है। यूपी ट्रेड शो ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, हेरिटेज और

इनोवेशन के संगम का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि २०१७ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने ही परंपरागत उद्यमों की ताकत को पहचाना था और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की सोच दी थी। टैलेंट और ट्रेडिशन को टेक्नोलॉजी से जोड़कर स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल ब्रांड बनाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के ७६ उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है और ७५ नये उत्पादों के लिए आवेदन किया गया है। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल, कन्नौज के इत्र और बनारस की सिल्क साड़ियां अब करोड़ों के कारोबार वाले ब्रांड बन चुकी हैं। एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट और फ्रेट क रिडोर ने बाजार तक पहुंच आसान की है। ट्रेड शो में जापान, वियतनाम, रूस, सिंगापुर, अस्ट्रिया और बेलारूस पार्टनर कंट्री हैं। उनके विशेष पवेलियन लगे हैं। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि के बाद सीएम ने अमित शाह को फिरोजाबाद के ओपल ग्लास से बनी राधा-ष्ण प्रतिमा भेंट की और 'एक जनपद एक व्यंजन' पोर्टल का शुभारंभ किया।

गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की 'तुम मेरे हो' का टीजर रिलीज

मुम्बई। गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय की फिल्म 'तुम मेरे हो' का बहुप्रतीक्षित टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में दोनों की गहरी और जुनूनी प्रेम कहानी की झलक देखने को मिलती है। आशीष पांडा निर्देशित 'तुम मेरे हो' में गुरमीत



और ईशा पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। टीजर में दोनों की केमिस्ट्री के साथ फिल्म के भावनात्मक दृश्यों और खूबसूरत विजुअल्स को दिखाया गया है। दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक टीजर के प्रभाव को और बढ़ाता है। 'तुम मेरे हो' ईशा मालवीय की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है। फिल्म का निर्माण रेवा क्रिएटिव हाउस और डेबगुरु

निरंजन अयंगर और पूर्वा नरेश ने लिखा है। फिल्म का संगीत मिथुन, संजू राठौड़, विवेक वर्मा, कृष, उद्दीपन शर्मा और अर्जुना हरजाई ने दिया है। फिल्म के गीत रश्मि विराग मिश्रा, मिथुन, अजीम शिराजी, संजू राठौड़, विवेक वर्मा और गीत सागर ने लिखे हैं। 'तुम मेरे हो' २३ अक्टूबर २०२६ को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

लखनऊ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर मार्च करने से रोके जाने पर पुलिस से उनकी झड़प हो गई। शुक्रवार को भारी बारिश के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस ने अवरोधक लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता अवरोधकों पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उनकी पुलिस से

झड़प हो गई। इसके बाद पुलिस ने राय, मिश्रा और प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर विरोध प्रदर्शन स्थल 'इको गार्डन' ले गई। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से एक पोस्ट में कहा लोकतंत्र की हत्या करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ज्ञानेश ने देशद्रोह का काम किया है, उन्हें चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश कांग्रेस ने एक अन्य पोस्ट में कहा जिन्हें लगता है हिरासत में लेकर आवाज दबा देंगे, वो गलतफहमी में हैं। यह आत्मविश्वास सत्ता के दमन पर सच की जीत का शंखनाद है प्रदर्शनकारियों ने बारिश के बीच

अपना आंदोलन जारी रखा, महिला कार्यकर्ता "वोट चोर, गद्दी छोड़" लिखे पोस्टर लिए हुए थीं। राय ने भाजपा और चुनाव आयोग पर साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हक की यह लड़ाई न रुकी है, न रुकेगी! लोकतंत्र पर हमला और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा गौतम ने भी कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की चुनावी गड़बड़ी देश हित के खिलाफ है। मिश्रा ने कहा कि हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी "वोट की चोरी" के आरोप लगे थे।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

संजय बाजपेई

सीतापुर

मो.9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

सुरेश नारायण मिश्र

क्षेत्रीय सम्पादक

सौरभ कुमार, बिहार

मो.09386075289

मो० अरशद

ब्यूरो चीफ

मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा साईं आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar @yahoo.in adbhut_samachar @rediffmail.com सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

माही श्रीवास्तव का 'नागिन जैसे डांस' वायरल

मुम्बई। भोजपुरी अभिनेत्री माही श्रीवास्तव का नया डांस गीत 'नागिन जैसे डांस' रिलीज के बाद दर्शकों के बीच चर्चा में है। गीत में माही अपने नृत्य और आकर्षक



अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं। गोल्डी यादव की आवाज में रिकॉर्ड किए गए इस गीत में माही नागिन की तरह लहराते और बलखाते हुए नृत्य करती नजर आ रही हैं। गीत के ऊर्जावान संगीत और माही के नृत्य ने इसे खास डांस नंबर बना दिया है। गीत का निर्माण वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के प्रबंध निदेशक एवं निर्माता रत्नाकर कुमार ने किया है। साइबस के निर्देशन में बने इस गीत के गीतकार एलसी प्रवीण

और संगीतकार आर्या शर्मा हैं। माही का मेकअप इंद्रजीत और हेयर स्टाइल पीहू ने किया है। निर्माता रत्नाकर कुमार ने कहा कि माही की अपनी अलग प्रशंसक संख्या है और 'नागिन जैसे डांस' में उन्होंने ऊर्जा और अंदाज के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गोल्डी यादव की आवाज और आर्या शर्मा के संगीत ने गीत को और खास बनाया है माही श्रीवास्तव ने कहा कि 'नागिन जैसे डांस' उनके लिए खास गीत है और इसमें उन्होंने अलग तरह के नृत्य का प्रयास किया है। उन्होंने गीत के लिए गोल्डी यादव, आर्या शर्मा और वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स की पूरी टीम का आभार जताया। गोल्डी यादव ने कहा कि यह ऊर्जावान और मनोरंजन से भरपूर डांस गीत है। माही के नृत्य और गीत की धुन का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है। 'नागिन जैसे डांस' वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक म्यूजिक चैनल पर रिलीज किया गया है।

लव एंड वॉर में आलिया भट्ट का लुक जारी

मुम्बई। संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वॉर' से आलिया भट्ट के दो पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। रणबीर कपूर के फर्स्ट लुक के बाद सामने आए आलिया के पोस्टर में उनका ग्लैमरस और रेड्रो अंदाज नजर आ रहा है पोस्टर में आलिया कुर्सी पर बैठी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आकर्षक स्लिट स्कर्ट के साथ हेडपीस पहना है। रिच बैकग्राउंड और रेड्रो अंदाज वाले पोस्टर में आलिया का लुक स्टाइलिश और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आता

है। 'लव एंड वॉर' में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल मुख्य भूमिकाओं में हैं। संजय लीला



भंसाली निर्देशित यह फिल्म २१ जनवरी २०२७ को हिंदी, तमिल और तेलुगु में दुनिया भर में रिलीज होगी।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक